(b) and (c) The State Governments have been directed to take legal action against all the defaulting units in January, 1993 and they have initiated action accordingly.

Spread of AIDS in the Country

*134. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned 'A million AIDS cases estimated in India-infection spreading' appeared in the Economic Times dated 14th January, 1992;

(b) what is the reaction of Government to this fast increasing disease;

(c) whether any steps have been taken to introduce compulsory testing for AIDS; and

(d) the reasons for inertia on the part of Government in combating AIDS?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANANAD): (a) Yes, Sir.

(b) Government has already taken up a comprehensive programme all over the country to prevent the spread of HIV infection in the country with assistance from the World Bank and the World Health Organisation.

(c) No, Sir. Government is not in favour of compulsory testing.

(d) Does not arises.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विदेशों से सहायता

*135. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने और इन राज्यों के प्रसंस्कृत फल-उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विदेशों से सहायता ले रही है;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1991 से अब तक इस दिशा में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों से ऐसे उत्पादों के निर्यात और उससे प्राप्त राजस्व तथा विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित करने हेतु राज्य-वार कितनी परियोजनाऐं लम्बित हैं और उन्हें कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) और (ख) जैतून का तेल निकालने की एक भारत-इटली एकीकृत परियोजना को हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्यों में इस समय इटली की सहायता से चलाया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कुछ खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में विदेशी/अनिवासी भारतीय एक्विटी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी है जिससे इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) पिछले चार वर्षों में देश से किया गया प्रसंस्कृत फल उत्पादों का निर्यात और अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है:—

करोड़ रुपये

1988-89	64.01
1989-90	77.21
1990-91	103.07
1991-92	120.00

(घ) इन राज्यों में ऐसे यूनिटों की स्थापना के कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में लम्बित नहीं हैं।

अफगानिस्तान से स्वदेश वापस आने वाले भारतीय

*136. **श्री सोम पाल:**
श्री शंकर दयाल सिंह:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफगानिस्तान से अब तक कितने भारतीय स्वदेश वापस आ गये हैं और उन भारतीयों की संख्या कितनी है जो स्वदेश वापस आने के इच्छुक हैं किन्तु अब तक वापस नहीं आ सके हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान की ओर से पूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण भारतीयों को स्वदेश वापस आने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) वे अपनी कुल कितनी सम्पत्ति अफगानिस्तान में छोड़कर आये हैं; और

(घ) उसे वापस दिलाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सड़कों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

*137. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य हेतु अब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वास्तव में व्यय की गयी धन-राशि सहित इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त धनराशि के व्यय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई पर्यवेक्षण/निगरानी की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस धनराशि को उचित ढंग से व्यय किया था?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) संवैधानिक तौर से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और विकास के लिए उत्तरदायी है अन्य सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रति वर्ष निधियों का आवंटन, संसाधनों की आवश्यकता एवं समग्र उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। पिछले दो वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए राज्यों द्वारा यथा सूचित आवंटन और खर्च निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	आवंटन	खर्च
1990-91	1108,51,000 रु०	1142,80,000 रु०
1991-92	1312,05,000 रु०	1366,62,000 रु०
1992-93 (दिसम्बर 92 तक)	1374,96,000 रु०	1065,30,000 रु०

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव संबंधी कार्यों के लिए राज्य सरकारें कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय का क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक वर्ष राज्य के लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर कार्य करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों की सतह के नवीनीकरण तथा सामान्य स्थिति संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है।

RSS propagation after Ban

*138. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite ban, RSS is running book-shops in Delhi and elsewhere and freely selling their literature and propagating their communal and Hindu Rashtra philosophy;

(b) whether Suruchi Prakashan is such a publisher in the Capital selling all such literature; and

(c) if so, why a banned organisation is permitted to carry out such activities?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a) to (c) According to Delhi Administration, the book shop by the name of 'Suruchi Prakashan' is found selling RSS literature on Hindu Rashtra philosophy in addition to other books. A case under Section 153A of the Indian Penal Code, and Section 10 of the Unlawful Activity (Prevention) Act, 1967 has been registered, and is under investigation.